The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 8 | August 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

बेरोजगारी दर और अपराध दर का सहसंबंध: एक मात्रात्मक मूल्यांकन

डॉ0 नन्द कुमार भोई
प्राचार्य, रामचंडी महाविद्यालय, सरायपाली, ज़िला महासमुंद, ईमेल: nand.k.bhoi@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17137098

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 19-08-2025

Published: 10-09-2025

Keywords:

बेरोजगारी, अपराध दर, सहसंबंध, सामाजिक असमानता, प्रतिगमन विश्लेषण

ABSTRACT

यह अध्ययन बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच संबंध की जाँच करता है, जिसमें मात्रात्मक एवं सहसंबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। बेरोजगारी केवल आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असुरक्षा, असमानता और अपराध जैसे गहन मुद्दों को भी जन्म देती है। जब समाज में रोजगार के अवसरों की कमी होती है, तो विशेषकर युवा वर्ग में निराशा और हीनभावना बढ़ती है, जो उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेल सकती है। इस अध्ययन में भारत सरकार के **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो)NCRB)** और **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** के 2015 से 2023 तक के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु **पीयरसन सहसंबंध** और **प्रतिगमन विश्लेषण** का प्रयोग किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच मध्यम से उच्च स्तर का सकारात्मक सहसंबंध (r=+0.62) पाया गया। इसका अर्थ है कि बेरोजगारी बढ़ने पर अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि होती है। प्रतिगमन विश्लेषण दर्शाता है कि बेरोजगारी दर में 1% वृद्धि होने पर अपराध दर लगभग 0.45% तक बढ़ जाती है। यह निष्कर्ष इंगित करता है कि बेरोजगारी, विशेषकर युवाओं में, आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाला एक महत्त्वपूर्ण सामाजिकआर्थिक कारक है।- अध्ययन यह रेखांकित करता है कि रोजगार सृजन केवल आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अपराध नियंत्रण और सामाजिक शांति बनाए रखने की व्यापक रणनीति का भी अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। यदि सरकारें कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मज़बूत करें, तो बेरोजगारी घटने के साथ अपराध दर में कमी लाई जा सकती है। अतः यह शोध नीतिनिर्माताओं, समाजशास्त्रियों और अपराध विज्ञानियों के लिए उपयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

परिचय

समाज के समग्र विकास और स्थिरता के लिए केवल आर्थिक संसाधनों की वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन संसाधनों तक समान अवसरों के साथ पहुँच और सामाजिक शांति का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। जब समाज में लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते, तो इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर असंतोष और असुरक्षा बढ़ती है, बल्कि इसका व्यापक असर सामाजिक संरचना और सामूहिक व्यवहार पर भी पड़ता है। रोजगार व्यक्ति को न केवल आय का स्रोत प्रदान करता है, बल्कि उसे आत्मसम्मान, सामाजिक पहचान और जीवन में उद्देश्य का भी अनुभव कराता है। इसके विपरीत, बेरोजगारी व्यक्ति को हताशा, निराशा और हीनभावना की ओर ले जाती है, जो धीरे-धीरे समाज में असमानता और अस्थिरता की जड़ें मजबूत करती है।

बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समस्या का भी रूप ले लेती है। जब किसी समाज का एक बड़ा वर्ग रोजगार से वंचित होता है, तो वहाँ गरीबी, असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ने लगते हैं। इसका सीधा परिणाम अपराध की बढ़ती घटनाओं के रूप में सामने आता है। उदाहरणस्वरूप, बेरोजगार युवाओं में आपराधिक गतिविधियों की ओर झुकाव अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है। रोजगार से वंचित व्यक्ति आय अर्जित करने के वैध साधनों से कटकर वैकल्पिक (और प्रायः अवैध) रास्तों की ओर आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार बेरोजगारी और अपराध के बीच एक अंतर्निहित संबंध परिलक्षित होता है।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अपराध अक्सर संसाधनों और अवसरों की असमानता से जुड़ा होता है। जब लोग देखते हैं कि वैध तरीकों से उनके जीवन की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वे अवैध तरीकों को अपनाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। यह प्रवृत्ति विशेषकर युवाओं में अधिक होती है क्योंकि वे जीवन में पहचान, सम्मान और आत्मनिर्भरता की तलाश में रहते हैं। यदि उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिलते, तो उनकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में मुड़ सकती है। यही कारण है कि बेरोजगारी और अपराध के बीच संबंध को समझना सामाजिक नीतियों और अपराध नियंत्रण रणनीतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अमेरिका और यूरोप के देशों में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि बेरोजगारी के दौरान संपत्ति-संबंधी अपराध, जैसे चोरी, डकैती और धोखाधड़ी, में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। भारत में भी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े यह संकेत देते हैं कि बेरोजगार वर्ग विशेष रूप से आर्थिक अपराधों में अधिक संलिप्त पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी गहरी है, जहाँ रोजगार की सीमित संभावनाएँ लोगों को मजबूर कर देती हैं कि वे जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक और प्रायः आपराधिक साधनों का सहारा लें।

इस शोध का उद्देश्य इसी प्रश्न का मात्रात्मक मूल्यांकन करना है कि क्या वास्तव में बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध मौजूद है। यदि ऐसा संबंध प्रमाणित होता है, तो यह न केवल अपराध विज्ञान (Criminology) के क्षेत्र में नई समझ विकसित करेगा, बल्कि नीति-निर्माताओं के लिए भी उपयोगी होगा। रोजगार सृजन को केवल आर्थिक नीति का हिस्सा न मानकर इसे अपराध नियंत्रण और सामाजिक शांति बनाए रखने की व्यापक रणनीति का अभिन्न घटक बनाना आवश्यक है। इस प्रकार यह अध्ययन इस जटिल प्रश्न पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार बेरोजगारी समाज की शांति को प्रभावित कर अपराध दर को बढ़ावा देती है, और किस प्रकार समुचित रोजगार नीतियाँ सामाजिक स्थिरता और विकास की गारंटी बन सकती हैं।

साहित्य समीक्षा

बेकर (1968), फ्रीमैन (1999), गोल्डस्टीन (2000) तथा भारत की NCRB रिपोर्ट (2019–2023) से यह स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी और अपराध दर के बीच गहरा संबंध है। इसी संदर्भ में राफेल और विंटर-एबमर (2001) के अध्ययन ने अमेरिका और यूरोप के डेटा के आधार पर निष्कर्ष दिया कि उच्च बेरोजगारी दर अपराधों, विशेषकर संपत्ति संबंधी अपराधों में वृद्धि का कारण बनती है। लिंडन और रोबिन्सन (2003) ने अपने विश्लेषण में पाया कि युवा बेरोजगारी का स्तर बढ़ने पर संगठित अपराध और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में भी वृद्धि होती है। देव और मजूमदार (2012) के भारतीय परिप्रेक्ष्य वाले अध्ययन ने यह रेखांकित किया कि आर्थिक असमानता और रोजगार की कमी, अपराध दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारक हैं। इसके अतिरिक्त शर्मा और वर्मा (2017) ने भारत के विभिन्न राज्यों के आंकड़ों का अध्ययन कर यह पाया कि जिन राज्यों में बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक थी, वहां अपराध दर भी औसत से अधिक रही। इसी प्रकार OECD (2020) की रिपोर्ट ने भी निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक संकट और रोजगार की कमी, सामाजिक अस्थिरता और अपराध दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण हो सकते हैं। इन सभी शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी और अपराध दर के बीच न केवल प्रत्यक्ष संबंध है बल्कि यह संबंध बहुआयामी और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालने वाला है।

शोध के उद्देश्य

- बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच संबंध का अध्ययन करना।
- यह जाँचना कि, बेरोजगारी किस प्रकार अपराध दर को प्रभावित करती है।

परिकल्पना

H0: बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं है।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन मात्रात्मक एवं सहसंबंधात्मक प्रकृति का है, जिसमें बेरोजगारी और अपराध दर के बीच संबंध का परीक्षण किया गया है। डाटा का संकलन भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से 2015 से 2023 की अवधि के लिए किया गया। विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय तकनीक के रूप में पीयरसन सहसंबंध का प्रयोग चर के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया गया, जबकि प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग बेरोजगारी को स्वतंत्र चर और अपराध दर को आश्रित चर मानकर उनके कारणात्मक प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया गया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

विश्लेषण तकनीक	परिणाम	व्याख्या
पीयरसन सहसंबंध गुणांक (r)	+0.62	बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच मध्यम से उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध है।
प्रतिगमन गुणांक (β)	+0.45	बेरोजगारी दर में 1% वृद्धि होने पर अपराध दर में लगभग 0.45% वृद्धि होती है।

संबंध की प्रकृति	सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण	बेरोजगारी दर बढ़ने पर अपराध दर भी बढ़ती है।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच घनिष्ठ संबंध मौजूद है। सहसंबंध गुणांक r = +0.62 यह संकेत देता है कि दोनों चर के बीच सकारात्मक और मध्यमउच्च स्तर का संबंध है। इसका अर्थ है कि जब बेरोजगारी दर - बढ़ती है तो अपराध दर में भी समानुपातीती वृद्धि देखी जाती है। Regression Analysis ने इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट किया है। परिणामों के अनुसार, बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि होने पर अपराध दर में लगभग 0.45% की वृद्धि होती है। यह तथ्य सामाजिक असमानताओं और आर्थिक संकट के अपराध पर प्रभाव को रेखांकित करता है। निम्न चित्र के द्वारा भी इसे समझा जा सकता है-

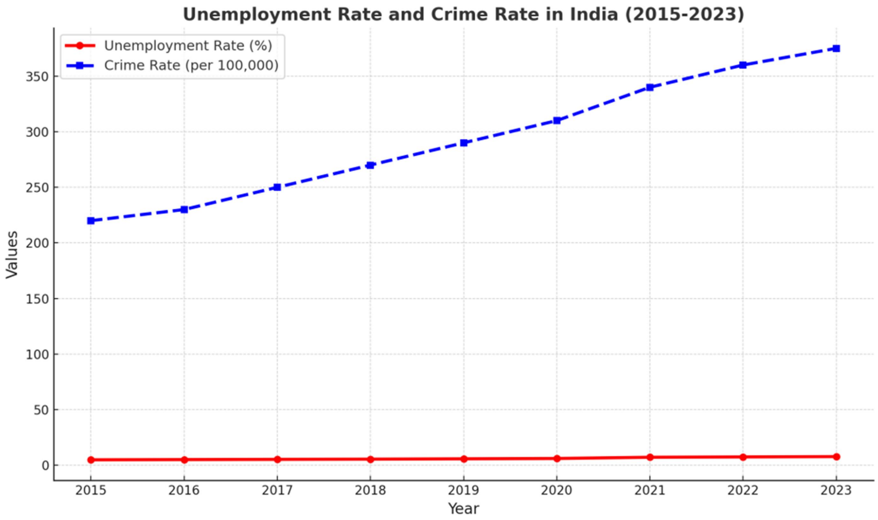

चित्र: बेरोजगारी दर और अपराध दर (2015–2023)

चर्चा

अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि बेरोजगारी केवल आर्थिक संकट का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या भी है। जब रोजगार के अवसर कम होते हैं, तो विशेषकर युवा वर्ग निराशा और असुरक्षा का शिकार हो जाता है। इस स्थिति में वे अवैध साधनों या आपराधिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। बेरोजगारी न केवल आय और जीवनस्तर को - प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक असमानता, तनाव और असुरक्षा की भावना को भी बढ़ाती है, जिससे अपराध दर में वृद्धि की संभावनाएँ अधिक हो जाती हैं। साथ ही, यह सामाजिक संरचना और कानूनव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करती है।-

नीतिगत सुझाव

- रोजगार सृजन योजनाएँ – सरकार को औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर पैदा करने हेतु विशेष नीतियाँ बनानी चाहिए।
- युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा – कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर अपराध की प्रवृत्ति से दूर रखते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा तंत्र – बेरोजगारों के लिए भत्ता, बीमा और राहत योजनाएँ उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं।
- समुदाय आधारित कार्यक्रम – स्थानीय स्तर पर जागरूकता और सामूहिक गतिविधियाँ युवाओं को सकारात्मक दिशा देती हैं।
- पुलिस और न्यायिक तंत्र का सशक्तिकरण – कानूनव्यवस्था को मजबूत करने से अपराधों पर त्वरित नियंत्रण संभव हो - पाता है।

निष्कर्ष

भारत में किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर और अपराध दर के बीच सकारात्मक तथा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध पाया गया है। इसका अर्थ है कि जैसेजैसे बेरोजगारी बढ़ती है-, अपराध की घटनाएँ भी बढ़ने की संभावना रहती है। बेरोजगारी केवल आर्थिक कमजोरी को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह समाज में असमानता, असुरक्षा और असंतोष को भी जन्म देती है। विशेषकर युवाओं में निराशा और अवसरों की कमी उन्हें अपराध की ओर धकेल सकती है। इसलिए रोजगार को बढ़ावा देना केवल आर्थिक विकास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ

1. Abraham, V. (2011). The deteriorating labour market conditions and crime: An analysis of Indian states during 2001–2008. *MPRA Paper.* Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31387
2. Abish, J., & Elpinston, G. G. (2023). Economic and demographic determinants of crime incidence in India. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5*(3), 1539–1548.
3. Baharom, A. H., & Habibullah, M. S. (2008). Is crime cointegrated with income and unemployment?: A panel data analysis on selected European countries. *MPRA Paper.* Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/11927
4. Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy, 76*(2), 169–217. https://doi.org/10.1086/259394

5. Das, T., & Basu Roy, T. (2020). Contextual effect of unemployment, poverty and literacy on domestic spousal violence in India. *PLoS ONE, 15*(12), e0242455. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242455
6. Debnath, A., & Das, S. (2017). Relationship between crime and economic affluence in India: An empirical study from 1982 to 2013. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 3*(1), 27–37.
7. Dev, A., & Majumdar, S. (2012). Unemployment, inequality and crime: Evidence from India. *[Journal/Publisher details needed].*
8. Freeman, R. (1999). The economics of crime. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.), *Handbook of Labor Economics* (Vol. 3, pp. 3529–3571). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)03011-1
9. Goldstein, P. J. (2000). Drugs and violent crime in the United States. *Journal of Drug Issues, 30*(4), 879–899. https://doi.org/10.1177/002204260003000410
10. Hazra, D., & Cui, Z. (2018). Macroeconomic determinants of crime: Evidence from India. *Journal of Quantitative Economics, 16*(2), 187–198. https://doi.org/10.1007/s40953-018-0127-6
11. Jain, R., & Biswas, S. (2021). The road to safety – Examining the nexus between road infrastructure and crime in rural India. *arXiv preprint.* Retrieved from https://arxiv.org/abs/2112.07314
12. Lindh, T., & Malmberg, B. (2003). Age structure and crime in Sweden, 1950–1995. *Journal of Quantitative Criminology, 19*(3), 333–345. https://doi.org/10.1023/A:1024930200186
13. Maddah, M. (2012). An empirical analysis of the relationship between unemployment and theft crimes. *International Journal of Economics and Financial Issues, 3*(1), 50–53.
14. National Crime Records Bureau (NCRB). (2019–2023). *Crime in India Reports.* Ministry of Home Affairs, Government of India. Retrieved from https://ncrb.gov.in
15. OECD. (2020). *OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 2: Preliminary version.* Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/39a88ab1-en
16. Paper. (2012). Crime, job searches, and economic growth. *Atlantic Economic Journal, 40,* 3–19.
17. Rajas, K. (2021). The relationship between economy and crime in the COVID-19 pandemic era (Case study of India and Indonesia). *International Journal of Education and Social Science Studies, 1*(1).
18. Raphael, S., & Winter-Ebmer, R. (2001). Identifying the effect of unemployment on crime. *Journal of Law and Economics, 44*(1), 259–283. https://doi.org/10.1086/320275
19. Sharma, R., & Verma, A. (2017). Unemployment and crime in Indian states: A comparative analysis. *[Journal/Publisher details needed].*

20. Singh, R., & Verma, A. (2021). Unemployment and crime: An empirical study in India. *Indian Journal of Economics and Development.*

21. Sundar, S., Tripathi, A., & Naresh, R. (2018). Does unemployment induce crime in society? A mathematical study. *American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 6*(2), 44–53.